सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

प्रधान संपादक: रतन प्रकाश सिंह

www.swarajindianews.com swarajindianews swarajindianews

स्वराज इंडिया

दैनिक सांध्यकालीन

कानपुर, गुरुवार, 25 सितम्बर, 2025
वर्ष: 02, अंक: 252, पृष्ठ: 8+4, मूल्य: ₹ 2/-

सपा में शामिल हुए अपना दल और बसपा के कई बड़े नेता

» Pg12

इनसाइड गौशालाओं की अव्यवस्था को लेकर एसडीएम सख्त... » Pg04

नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ

चिप से शिप तक बनाएंगे, निर्भर रहना अब मंजूर नहीं

पीएम मोदी ने की यूपी सरकार की तारीफ, कहा- देश के 55 प्रतिशत मोबाइल फोन यूपी में बन रहे

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

नोएडा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज से आगाज हो गया है। ग्रेटर नोएडा में हो रहे इस ट्रेड शो में प्रदेश के उद्यमियों को वैश्विक मंच मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज उद्घाटन किया। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश की मौजूदा ग्रोथ को बेहद आकर्षक बताया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश को अब किसी देश पर निर्भर नही रहना है। जो हम भारत मे बना सकते है उसे भारत मे ही बनाएंगे। जो भी मेन्युफेक्चरिंग में बनाया जा रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज देश का हर नागरिक स्वदेशी से जुड़ रहा है। जो भारत मे उपलब्ध है उसे ही प्राथमिकता देनी है। हमें

» पहले 1,000 की शर्ट पर 117 रुपये टैक्स लगता, जीएसटी लागू होने के बाद हुआ 50 रुपए।

स्वदेशी का पूरा इको सिस्टम बनाना है। आज भारत मे जितने फोन बनते है उसके 55 प्रतिशत यूपी में बन रहे हैं। पुर्जे-पुर्जे पर मेक इन इंडिया की छाप हो हम ऐसा इको सिस्टम बना रहे हैं। यूपी इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी पर काम शुरू होने वाला है।

पीएम ने कहा कि हमारी सेनाएं स्वदेशी चाहती हैं और दूसरों पर निर्भरता को कम करना चाहती हैं। इसलिए हम भारत में ही एक वाइब्रेंट डिफेंस सिस्टम विकसित कर

वैश्विक व्यापार का महाकुंभ

रहे हैं। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि यूपी में निवेश कीजिए, यूपी में मैन्युफैक्चर कीजिए। यहां लाखों एमएसएमई का मजबूत नेटवर्क है, उनके सामर्थ्य का इस्तेमाल कीजिए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं तैयार कीजिए। इसके लिए हर मदद के साथ यूपी सरकार और भारत सरकार आपके साथ है। 2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे कि बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट कभी संतुलित नहीं हो पाते थे। इसे संतुलित करना मुश्किल था। 2014 में 1,000 रुपये की शर्ट पर 117 रुपये टैक्स लगता था। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स घटकर 50 रुपये हो गया।

हम विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ!

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड शो के उद्घाटन के दौरान कहा कि इस ट्रेड शो का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भर बनाना है। 'मेक इन इंडिया' पर हमारा जोर है. हम किसी भी चीज को लेकर दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। चिप से शिप तक भारत में ही बनाना चाहते हैं. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने बताया कि इस बार इंटरनेशनल ट्रेड शो में रूस भारत का साझेदार होगा।

जीएसटी रिफॉर्म से बाजारों में रौनक लौटी है: सीएम योगी

कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसी साल नवंबर के महीने में यूपी में करेंगे 5 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। प्रदेश के हर जिले में 100 एकड़ जमीन में आद्योगिक विकास कार्य होंगे। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, इस ट्रेड शो में एक मंच पर व्यापारी और खरीददार मौजूद हैं। जो निवेश आ रहा है, उससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म किया है, उससे देश के बाजारों में रौनक लौट आई है।

बड़ी राहत — पूर्व विधायक और उनके भाई रिजवान की हाईकोर्ट से बेल मंजूर

इरफान सोलंकी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, मिली जमानत

» प्रयागराज, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में भी उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच इरफान की याचिका मंजूर करते हुए उनके भाई रिजवान को भी राहत दी है। रिजवान की याचिका भी मंजूर हो गई है। इरफान दो साल से जेल की सलाखों में हैं। कानपुर की शीशामऊ सीट से इरफान विधायक थे। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। उपचुनाव में इरफान की पत्नी ही यहां से विधायक चुनी गई थीं।

इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला के खिलाफ कानपुर के जाजमऊ थाने में 26 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि इरफान सोलंकी ने गैंग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए आम जनता को भयभीत किया। इस मामले में इरफान सोलंकी पिछले 24 महीनों से महाराजगंज जेल में बंद हैं, जबकि अन्य चार आरोपी कानपुर जेल में हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 सितंबर 2025 को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इरफान सोलंकी की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने दलीलें पेश कीं, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत का विरोध किया।

अन्य मामलों में भी जमानत

इरफान सोलंकी को हाल ही में अन्य मामलों में भी जमानत मिल चुकी है। मार्च 2025 में रंगदारी के एक मामले में उन्हें और उनके भाई रिजवान सोलंकी को जमानत मिली

थी। इसके अलावा, 1 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने के आरोप में उन्हें जमानत मिली थी। इसके अलावा इरफान सोलंकी को जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा के घर में आगजनी के मामले में कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 7 जून 2024 को सात साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 14 नवंबर 2024 को जमानत तो दी, लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उनकी विधायकी बहाल नहीं हो सकी।

समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री ने लगाई अफसरों की क्लास

» सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री का सख्त रुख, अफसरों को लगाई फटकार

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। सरकारी योजनाओं और कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अफसरों की जमकर क्लास लगाई। सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में हुई बैठक में मंत्री ने साफ कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में चौबेपुर व बिल्हौर के बीडीओ पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। चौबेपुर बीडीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई, वहीं बिल्हौर बीडीओ को हटाने के आदेश हुए। जनप्रतिनिधियों के फोन न उठाने की शिकायत पर मंत्री ने चेताया कि ऐसे अफसरों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण अधिकारी की अनुपस्थिति पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए।

क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत करे मेट्रो प्रबंधन

महापौर प्रमिला पांडेय की शिकायत पर मंत्री ने यूपीएमआरसी को घेरा। कहा कि मेट्रो निर्माण से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत कराई जाएगी और जरूरत पड़ने पर किराया भी यूपीएमआरसी वहन करेगी। घाटमपुर तक समयबद्ध कार्य पूरा करने का भी निर्देश दिया।

सीएमओ से नाराज दिखे मंत्री

बैठक में सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी को कुर्सी तक नसीब नहीं हुई।

देर से आने पर उन्हें सीडीओ के कहने पर किसी अफसर की कुर्सी मिल सकी। मंत्री ने उनसे सीएचसी-पीएचसी में डॉक्टरों की रात्रि उपस्थिति पूछी तो वे गोलमोल जवाब देने लगे।

नाराज मंत्री ने कहा – प्रवक्ता हो क्या? जितना पूछा है उतना बताओ। इसके बाद सीएमओ जवाब नहीं दे पाए। मंत्री ने सभी चिकित्सकों को तैनाती स्थल पर ही निवास करने के निर्देश दिए और डीएम को रात में निरीक्षण करने को कहा।

कानून व्यवस्था और यातायात पर सख्ती

मंत्री ने पुलिस कमिश्नर को महिला अपराधों पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

हेलमेट नियम सख्ती से लागू करने, ई-रिक्शा और अतिक्रमण पर कार्रवाई तथा ऑटोमैटिक स्पीड सेंसर से चालान व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया।

अन्य निर्देश भी जारी किए गए

भीख माँगने की समस्या पर फजलगंज व विजय नगर में विशेष अभियान चलाने का आदेश।
नगर निगम अस्पतालों का कायाकल्प कराने व नौबस्ता के 100 बेड के अस्पताल में जल्द स्टाफ नियुक्त करने का आश्वासन।
बाजारों के गंदे शौचालय एक सप्ताह में साफ कराने व 40 पिंक टॉयलेट शुरू करने का आश्वासन।
खाद वितरण में अनियमितता पर एआर कोऑपरेटिव को फटकार और जांच के निर्देश।
बैठक में सांसद अशोक रावत, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, नगर आयुक्त सुधीर कुमार, सीडीओ दीक्षा जैन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

चोरनी समझ सेल्स गर्ल को बनाया बंधक, पुलिस ने कराया मुक्त

» महिला बोली जबरन घुसी घर में गाली-गलौज की

» युवती का आरोप बंधक बनाकर मारपीट की गई

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कल्याणपुर के बारासिरोही इलाके में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कंपनी के उत्पाद बेचने गई एक युवती को सीआरपीएफ जवान की पत्नी ने घर में बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को मुक्त कराया। देर शाम तक दोनों पक्ष चौकी में आमने-सामने बैठे रहे और एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहे।

जानकारी के अनुसार कल्याणपुर निवासी युवती एक कंपनी के उत्पाद बेचने के लिए अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गई थी। बाद में टीम के सदस्य अलग हो गए और युवती अकेली बारासिरोही की एक गली में पहुंची।

वहां उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। घर की महिला, जो सीआरपीएफ जवान की पत्नी है, ने आरोप लगाया कि युवती जबरन घर में घुस आई और गाली-गलौज करने लगी। इसी पर उन्होंने युवती को घर में बंद कर लिया।कुछ देर बाद युवती ने अपने सहकर्मियों को जानकारी दी। साथी मौके पर पहुंचे और हंगामा खड़ा कर दिया।

पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद फोर्स पहुंचा और युवती को बाहर निकाला गया। वहीं, युवती का आरोप है कि महिला ने उसे बंधक बनाकर मारपीट की। उधर, महिला का कहना है कि क्षेत्र में चोरियों का डर है और युवती संदिग्ध ढंग से घर में घुसी थी। इसको लेकर दोनों पक्ष चौकी पहुंच गए, जहां देर रात तक विवाद चलता रहा।एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर ली गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई सबूतों व तथ्यों के आधार पर की जाएगी।

नगर निगम पार्क में डांडिया नाइट पार्टी पर रोक, स्वराज इंडिया की खबर का बड़ा असर

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम के पार्कों में निजी आयोजनों और व्यावसायिक उपयोग पर रोक के बावजूद इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। ताज़ा मामला जोन-5 के वार्ड 57 अंतर्गत पनकी बी ब्लॉक स्थित नगर निगम पार्क का है। यहां 25 सितंबर को डांडिया नाइट का आयोजन किया जाना था। पोस्टर तक जारी कर दिए गए थे और एंट्री पास भी बेचे जा रहे थे।सूत्रों के अनुसार, आयोजकों द्वारा प्रति व्यक्ति 150 का टिकट और परिवार के लिए 500 का पास रखा गया था, जिसमें चार लोगों की एंट्री हो सकती थी।

» नगर आयुक्त सुधीर कुमार के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की तैयारी

» नगर निगम ने पनकी पुलिस को भेजा पत्र

बताया जा रहा था कि कार्यक्रम में साढ़े तीन सौ से अधिक लोगों को प्रवेश दिया जाना था और शाम 6 बजे से देर रात तक रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी।

इस पूरे प्रकरण को लेकर जब स्वराज इंडिया संवाददाता ने आयोजक सोमेंद्र दुबे से संपर्क किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि 卐श्रीराम स्कूल के पीछे स्थित पार्क में आयोजन की तैयारी की जा रही है卐। लेकिन नगर निगम से अनुमति के सवाल पर वे सकपका गए और कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए।

नगर निगम के उच्चाधिकारियों तक शिकायत पहुंचने के बाद विभाग हरकत में आया। उद्यान विभाग के सुपरवाइज़र को मौके पर भेजा गया और पनकी थाना प्रभारी को पत्र लिखकर कार्यक्रम रुकवाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने माना कि नगर निगम पार्कों का व्यावसायिक इस्तेमाल न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि यह कोर्ट की गाइडलाइंस का भी उल्लंघन है।

स्वराज इंडिया की खबर का बड़ा असर यह रहा कि नगर निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पार्क में हो रही तैयारी रुकवाई और पुलिस को भी हस्तक्षेप के लिए पत्र लिखा। अब सवाल यह है कि नगर निगम पार्कों में धड़ल्ले से हो रहे ऐसे आयोजनों को रोकने के लिए स्थायी और कड़े कदम कब उठाए जाएंगे।

स्वराज इंडिया कानपुर सिटी 03

(सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन्स का उल्लंघन)

नगर निगम पार्क बना व्यवसायिक कार्यक्रमों का अड्डा !

» जोन-5 के वार्ड 57 के अंतर्गत पनकी स्थित नगर निगम पार्क में डांडिया पार्टी के लिए की गई बुकिंग

» 25 सितंबर के आयोजन के लिए आयोजक वसूल रहे लाखों रुपए

वार्ड-70 कर्रही में सीवर व जल समस्या बेहाल

निरीक्षण कर अधिकारियों ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। दक्षिण कानपुर के कर्रही वार्ड-70 समेत आसपास के इलाकों में लंबे समय से सीवर जाम, नाला भराव और स्वच्छ पानी सप्लाई की समस्या बनी हुई है।

इसी क्रम में आज जल संस्थान के महाप्रबंधक, अधिशासी अभियंता दिवाकर भास्कर और उनकी पूरी टीम ने मौके पर पहुंचकर समस्याओं का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान बर्रा बाईपास के नीचे विगत कई दिनों से हो रहे सीवर व नाले के भराव तथा पानी की अनियमित सप्लाई को लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानियां साझा कीं।

क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि आए दिन नाले का पानी सड़कों पर फैलने से आने-जाने में भारी दिक्कत हो रही है।

अधिकारियों ने गुंजन विहार, बर्रा साउथ सेक्टर, विश्व बैंक क्षेत्र और बर्रा बाईपास रोड का निरीक्षण कर आश्वासन दिया

कि अति शीघ्र इन समस्याओं का निदान किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान कर्रही वार्ड-70 के पार्षद संतोष साहू, सामाजिक कार्यकर्ता ऋषि बाजपेई, संतोष राजपूत, अमरीश त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को बाध्य होंगे।

बैठक में गूंजा किसानों की खाद किल्लत व टूटी सड़कों का मुद्दा

अवकाश सिंह ने फ्लाईओवर और स्टेडियम निर्माण की रखी मांग

विकास कार्य योजना समिति की बैठक

» खेल सुविधाओं व युवा विकास के लिए भी रखी गई मांगें।

बैठक में घिमऊ जिला पंचायत सदस्य अवकाश सिंह व अन्य।

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। जिला कार्य योजना समिति की बैठक में बुधवार को विकास से जुड़े कई अहम मुद्दे छाए रहे। बैठक में किसानों, युवाओं और आमजन की समस्याओं को विस्तार से रखा गया। घिमऊ क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य अवकाश सिंह उर्फ अंकुश ने कहा कि आलू की बुवाई प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन सहकारी समितियों में डीएपी खाद की अनुपलब्धता से किसान बेहाल हैं। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते खाद की आपूर्ति नहीं हुई तो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इसके साथ ही बारिश के बाद टूटी लोकनिर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत न होने से जनता को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। चौबेपुर के मरियानी मोड़ पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने फ्लाईओवर निर्माण की मांग रखी। इस पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने भरोसा दिलाया कि किसानों को खाद की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी और किसी भी समस्या पर तुरंत प्रशासन को सूचित किया जा सकता है।

युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अवकाश सिंह ने डो?वा जमौली, नदिहा व सखरेज न्याय पंचायतों में स्टेडियम निर्माण की मांग शासन से की और ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में वे पीछे रह जाते हैं। समिति के अन्य सदस्यों ने भी स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, पेयजल आपूर्ति, रोजगार सृजन और महिला सुरक्षा पर जोर दिया।

बैठक में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, सांसद मिश्रिख अशोक रावत, सांसद रमेश अवस्थी, महापौर प्रमिला पांडेय, विधायक सुरेंद्र मैथानी, पुलिस आयुक्त अखिल कुमार समेत विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी विभाग मिलकर जनता की समस्याओं के समाधान और क्षेत्रीय विकास के लिए ठोस कदम उठाएंगे।

आजम खान की रिहाई पर सपाइयों ने जताई खुशी, बांटी मिठाइयां

बोले कार्यकर्ता- पार्टी में नई ऊर्जा का हुआ संचार

मकनपुर मे सपाइयों ने मिठाई बांटकर दुआएं मांगी।

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर(कानपुर)। समाजवादी पार्टी के बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान की रिहाई पर हर्ष जताते हुए कार्यकर्ताओं संग मिष्ठान वितरण किया। इस दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं व स्थानीय नागरिकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर उल्लास व्यक्त किया।विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आजम खान समाजवादी आंदोलन के मजबूत स्तंभ रहे हैं। उन्होंने हर वर्ग की आवाज़ बुलंद करने के साथ-साथ शिक्षा, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को नई दिशा दी। रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना उनका ऐतिहासिक योगदान है, जिसने वंचित व पिछड़े वर्गों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा।

उन्होंने कहा कि आजम खान की रिहाई से सपा परिवार में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और समाजवादी आंदोलन को मजबूती मिलेगी। कहा कि आजम खान सपा की विचारधारा के सच्चे वाहक और संघर्ष के प्रतीक हैं। उनका पूरा जीवन गरीबों, किसानों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई को समर्पित रहा है।

उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई से पार्टी की आवाज और बुलंद होगी। इधर मकनपुर में अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष मुकीम कहां,वरिष्ठ सपा नेता वासिफ हुसैन जाफरी एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की और आजम खान के लिए दुआएं की। इस दौरान सपा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मीना का जन्मदिन स्कूलों में उत्साह से मनाया गया

बालिका शिक्षा और अधिकारों पर बच्चों ने दिए संदेश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर नगर) सरकारी स्कूलों में मीना का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यह दिन लड़कियों की शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। मीना एक काल्पनिक पात्र है, जो यूनिसेफ द्वारा बनाए गए एक आंदोलन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बच्चों और विशेष रूप से लड़कियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है।

मीना के जन्मदिन पर स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. बच्चों ने मीना के जन्मदिन पर केक काटकर जश्न मनाया। छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए, जिसमें उन्होंने बालिका शिक्षा और अधिकारों के प्रति अपने विचार व्यक्त किए. मीना के माध्यम से बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के महत्व के बारे में बताया गया मीना के जन्मदिन पर बच्चों को बाल विवाह, भेदभाव और शिक्षा की कमी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया।

इस अवसर पर स्कूलों में उपस्थित शिक्षकों और अधिकारियों ने मीना के संदेश को आगे बढ़ाने और समाज में बेटियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम करने का संकल्प लिया। मीना का जन्मदिन एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो हमें समाज में लड़कियों के अधिकारों और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करता है

गौशालाओं की अव्यवस्था को लेकर एसडीएम सख्त

अधिकारियों को चेतावनी, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

» अनुश्रवण एवं समीक्षा बैठक में चारा-पानी और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर दिए निर्देश।

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर(कानपुर)। तहसील क्षेत्र की गौशालाओं में व्याप्त अव्यवस्थाओं और कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एसडीएम संजीव दीक्षित की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में पशुपालन, राजस्व, पंचायत सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान गौशालाओं में चारे-पानी की कमी, साफ-सफाई और पशुओं की स्वास्थ्य जांच की लापरवाहियों पर एसडीएम ने नाराज़गी जताई। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि गौशालाओं में मूलभूत सुविधाओं की कमी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी गौवंश को पर्याप्त मात्रा में आहार, स्वच्छ पानी और चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो। एसडीएम ने चेतावनी दी कि यदि कहीं भी लापरवाही सामने आई तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गौशालाओं को आदर्श स्वरूप में लाने के लिए विभागीय तालमेल अनिवार्य है। इस मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी एसके द्विवेदी, बीडीओ बिल्हौर समेत संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

सम्पादकीय

पहाड़ी इलाके में विकास-रोजगार की आकांक्षा

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा देने व संविधान के अंतर्गत विशेष संरक्षण देने वाली छठी अनुसूची में शामिल करने के लिये चल रहे आंदोलन का हिंसक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल, पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बीते पंद्रह दिनों से अनशन पर थे। इन्हीं मुद्दों के समर्थन में यह आंदोलन चल रहा था। हालांकि, हिंसा के बाद उन्होंने अपना अनशन त्याग दिया है। उन्होंने आंदोलनकारियों से शांति की अपील की है। हिंसा व आगजनी के बाद केंद्र शासित प्रदेश में संचारबंदी लागू की गई है। समाचार माध्यमों में कुछ आंदोलनकारियों के मारे जाने की बात भी कही जा रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्रशासित प्रदेश में लद्दाख को पूर्ण राज्य देने की मांग को लेकर समय-समय पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। बताया जाता है कि पिछले पैंतीस दिनों से कुछ लोग अनशन कर रहे थे। परसों उनमें से दो लोगों की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ा। प्रतिक्रिया स्वरूप लेह बंद का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। यह प्रदर्शन कालांतर हिंसक प्रतिरोध में बदल गया। घटनाक्रम के बाद जम्मू-कश्मीर के विपक्षी दलों ने हिंसा के लिये केंद्र को निशाने पर लिया है। कहा गया कि आंदोलनकारी लेह की अस्मिता को संरक्षण देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र व लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच आगामी माह में एक वार्ता का दौर निर्धारित था,लेकिन आंदोलनकारी इससे पहले ही इस दिशा में पहल की मांग करते रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के विपक्षी दलों के नेता लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद लोगों की आकांक्षा पूर्ण न होने पर उपजे आक्रोश को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि लेह के लोग अधूरे वायदों से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से आंदोलनकारियों की हिंसक अभिव्यक्ति सामने आई है।जम्मू-कश्मीर के विपक्षी नेताओं द्वारा सवाल उठाये जा रहे हैं कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने पर जश्न मनाने वाले लद्दाख के लोगों में आज आक्रोश क्यों पनप रहा है? वे इस अभिव्यक्ति के आलोक में जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को फिर वापस लौटने की भी मांग कर रहे हैं। निस्संदेह, लेह चीन की सीमा से लगा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, जिसके मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि लेह के आंदोलनकारी कई सालों से भूमि संरक्षण व संस्कृति की रक्षा के लिये इस केंद्रशासित प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची का कवच देने तथा पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। उनका कहना था कि केंद्र शासित प्रदेश बनने से क्षेत्र के लोगों की आंकाक्षा पूरी नहीं हुई। एक बड़ा मुद्दा क्षेत्र के युवाओं की बेरोजगारी रही है। युवाओं की दलील है कि क्षेत्र के युवाओं को पहले जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विस सेलेक्शन कमीशन में राजपत्रित अधिकारी पदों के लिये आवेदन का मौका मिलता था, जो लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बंद हो गया। स्थानीय युवा अब केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की स्पर्द्धा में टिक पाने में दिक्कत महसूस करते हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय नौकरियों में युवाओं के लिये कोई विशेष अभियान भी नहीं चला। जिससे बेरोजगारों में खासा रोष व्याप्त रहा है। वहीं लद्दाख की अस्मिता को संरक्षित करने के लिये छठी अनुसूची की मांग लंबे समय से की जाती रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भाजपा ने वर्ष 2019 के घोषणापत्र में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने का वायदा किया था। लेकिन अब इस पर आनाकानी की जा रही है। आंदोलनकारी इसके अलावा कारगिल व लेह को लोकसभा सीट बनाने और स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने की भी मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 244 की छठी अनुसूची में ऐसी स्वायत्त व अधिकार संपन्न प्रशासनिक इकाइयों का प्रावधान है।

जाति रहित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण पहल

डा0 जोगिन्दर सिंह

उत्तर प्रदेश में हाल में जारी प्रशासनिक आदेश समाज में एकजुटता लाने का वादा करता है। लेकिन सफलता इसकी सख्ती व निष्पक्षता पर निर्भर होगी। यदि ऐसा हुआ तो यह राजनीति विकास-केंद्रित बनाने का रास्ता खोलेगा। पार्टियां नीतिगत मुद्दों जैसे रोजगार, शिक्षा पर फोकस करेंगी।उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, हमेशा से ही जाति की राजनीति का केंद्र रहा है। यहां की 80 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती हैं, और जातिगत समीकरण चुनावी दांव-पेच का आधार बनते हैं।हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जो इस पुरानी परंपरा को चुनौती दे रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में, राज्य सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड्स, सार्वजनिक स्थानों, वाहनों और सोशल मीडिया पर जाति के उल्लेख पर प्रतिबंध लगा दिया। एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और सरकारी दस्तावेजों में अब आरोपी या पीड़ित की जाति नहीं लिखी जाएगी। जाति-आधारित रैलियों, स्टिकर, साइनबोर्ड और नारेबाजी पर सख्ती बरती जाएगी, हालांकि एससी/एसटी अत्याचार निवारण एक्ट के मामलों में अपवाद रहेगा।

सरकार का यह कदम न केवल प्रशासनिक सुधार का हिस्सा है, बल्कि गहरी सामाजिक और राजनीतिक रणनीति का संकेतक है। क्या यह जातिवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है?

उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति पर टिकी है। यहां यादव, जाटव, कुर्मी, गुर्जर, ब्राह्मण और राजपूत जैसे समूह वोट बैंक का आधार हैं।

सपा और बसपा जैसी पार्टियां तो जाति पर ही निर्भर हैं। सपा का 'पिछड़ा, दलित और मुस्लिम' फॉर्मूला और बसपा का 'बहुजन' एजेंडा जाति-आधारित रैलियों-सम्मेलनों पर है। हाल में सपा का गुर्जर सम्मेलन इसी रणनीति का हिस्सा था, लेकिन अब यह संभव नहीं रहेगा।

अखिलेश यादव ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह केवल दिखावा है; असली भेदभाव मन में बसे 5000 साल पुराने जातिवाद को मिटाने के लिए क्या किया है? वहीं सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। वहीं भाजपा का 'हिंदुत्व' एजेंडा जाति से ऊपर उठ हिंदू एकता पर जोर देता रहा है।

'बंटोगे तो कटोगे' का नारा इसी का प्रतीक है। वर्ष 2024 उपचुनावों में कुंदरकी जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर राजपूत उम्मीदवार की जीत इसका उदाहरण है। लेकिन छोटी जातिगत सभाओं (जैसे ब्राह्मण या राजपूत महासभाओं) की बढ़ती सक्रियता भाजपा को चुनौती भी है। यह फरमान इन सभाओं को कुचल सकता है, जिससे भाजपा का हिंदू वोट बैंक मजबूत होगा। राष्ट्रीय स्तर पर जहां जाति जनगणना 2025 का मुद्दा गर्म है, यह कदम भाजपा को 'सामाजिक समरसता' का चेहरा देगा। बिहार चुनाव में जाति जनगणना का उपयोग विपक्ष के विरुद्ध हो सकता है। हालांकि, लंबे समय में यह राजनीति को 'विकास-केंद्रित' बनाने का रास्ता खोलेगा। पार्टियां नीतिगत मुद्दों जैसे रोजगार, शिक्षा पर फोकस करेंगी, जो लोकतंत्र के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर लागू न हुआ, तो विपक्ष को 'जातिवादी साजिश' का हथियार दे देगा।

जाति उत्तर प्रदेश के समाज का केंद्रीय तंतु है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की 20 प्रतिशत आबादी एससी/एसटी है, 40-50 प्रतिशत ओबीसी और बाकी सवर्ण। लेकिन यह विभाजन हिंसा का कारण भी बनता है। यह आदेश ऐसी हिंसा कम करने में मदद कर सकता है।

एफआईआर में जाति न लिखने से 'जातिगत अपराध' के आंकड़े कम दिखेंगे, जो पूर्वाग्रह कम करेगा। सार्वजनिक स्थानों से जातीय संकेत हटने से सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर निगरानी से ऑनलाइन घृणा फैलाने वाले अभियान रुक सकते हैं। यह युवाओं को जाति से ऊपर उठने को प्रेरित करेगा, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां विकास, शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन इस राह में चुनौतियां भी हैं। एफआईआर में जाति न लिखने से एससी/एसटी एक्ट के तहत न्याय मिलना मुश्किल हो सकता है। गांवों में प्रतिरोध पैदा कर सकता है। ऊपरी जातियों की सभाएं प्रभावित होंगी, जो 'अभिव्यक्ति की आजादी' का सवाल उठा सकती हैं। अगर लागू न हुआ, तो यह सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है।

यह फरमान उत्तर प्रदेश को 'जाति-रहित' समाज की ओर ले जाने का वादा करता है, लेकिन सफलता सख्ती और निष्पक्षता पर निर्भर करेगी। राजनीतिक रूप से, यह भाजपा को मजबूत कर विपक्ष को बैकफुट पर ला सकता है, सामाजिक रूप से हिंसा कम करने और समरसता बढ़ाने का मौका देगा। लेकिन बिना शिक्षा, आर्थिक समानता आदि के ठोस परिणाम नहीं देगा। भारतीय संविधान की भावना 'समानता' की है। अगर यूपी यह मॉडल अपनाता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जाति की राजनीति कमजोर हो सकती है। इतिहास सिखाता है कि जाति आसानी से नहीं जाती। फिलहाल, यह एक साहसिक कदम है—समाज को एकजुट करने का।

ग्रामीण सरोकारों के अग्रदूत रहे चौ. देवीलाल

चौ. देवीलाल

केसी त्यागी

चौ. देवीलाल ने अपने समर्पित जीवन से ग्रामीण भारत, खासकर किसानों और मजदूरों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। वे लोकदल के प्रमुख नेता थे जिन्होंने चौ. देवीलाल ने अपने समर्पित जीवन से ग्रामीण भारत, खासकर किसानों और मजदूरों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। वे लोकदल के प्रमुख नेता थे जिन्होंने गैर-कांग्रेसी आंदोलन को संगठित किया और हरियाणा की राजनीति में नए परिवर्तन लाए। उनकी सादगी और तपस्या आज भी प्रेरणादायक है।नौ अगस्त, 1974 को चौ.चरण सिंह के नेतृत्व में लोकदल का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य केंद्र में सत्तारूढ़ इंदिरा सरकार के विरुद्ध एक मजबूत विकल्प तैयार करना था। वर्ष 1971 के चुनाव में सभी विपक्षी दल धराशायी हो चुके थे। चौ. चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मधुलिमये, राज नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, बलराज मधोक आदि नेता पराजित हो गए थे।

इंदिरा सरकार मनमाने तरीके से फैसले लेकर अधिनायकवादी हो रही थी। देश के लगभग सभी राज्यों में कांग्रेसी सरकारें थीं। पंजाब के बंटवारे के बाद उन दिनों चौ. बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और इंदिरा परिवार के करीबी लोगों में उनकी गिनती होती थी। गुड़गांव में 250 एकड़ जमीन संजय गांधी मारुति कंपनी को अलॉट कर काफी ख्याति प्राप्त कर चुके थे। एक अक्खड़ और दबंग राजनेता की छवि वे बना चुके थे।लोकदल में शामिल नेताओं की लंबी फेहरिस्त बन गई।

उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके बीजू पटनायक, स्वतंत्र पार्टी के नेता एवं सांसद पीलू मोदी, जयपुर की महारानी गायत्री देवी, राजस्थान के किसान नेता चौ. कुंभाराम आर्य और चौ. दौलत राम सारण, समाजवादी आंदोलन के शीर्षस्थ नेता राज नारायण, कर्पूरी ठाकुर, मामा बालेश्वर दयाल, रवि राय, रामसेवक यादव, मुलायम सिंह यादव आदि नेता अपने समर्थकों के साथ नए विकल्प को मजबूत करने में जुटने लगे। उस समय जनसंघ (अब भाजपा) संगठन के तौर पर अपनी उपस्थिति जोरदार तरीके से दर्ज नहीं कर पा रहा था। अटल जी अवश्य राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रखर वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। जनसंघ के कई नामी गिरामी नेता भी लोकदल में शामिल हो चुके थे। जिसमें पूर्व अध्यक्ष बलराज

मधोक, पीतांबर दास और एम.एल. सोंधी आदि थे। हरियाणा और पंजाब में किसान मजदूरों के कई आंदोलन जोर पकड़ रहे थे। स. प्रकाश सिंह बादल और चौ. देवीलाल किसानों के सवालों पर रोज पंचायत आयोजित कर सरकार की परेशानियां बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर चौ. चांदराम हरियाणा के दलितों को एकताबद्ध कर राज्य और केंद्र सरकार की नयी घेराबंदी में लगे थे। चौ. देवीलाल और चौ. चांदराम दोनों के लोकदल में शामिल होने से हरियाणा की राजनीति में मानो भूचाल आ गया था। बंसीलाल के आतंक का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं था। कांग्रेस पार्टी की राजनीति में चौ. देवीलाल, चौ. बंसीलाल के सीनियर नेता थे। चौ. देवीलाल का परिवार आजादी के संग्राम में अग्रणी था। यद्यपि उस समय सर छोटू राम का समूचे पंजाब के किसानों पर बेहद असर था।जमींदारा पार्टी किसान हितों की एकमात्र पार्टी मानी जाती थी। हिसार में चौ. देवीलाल और रोहतक में चौ. रणबीर सिंह (भूपेंद्र हुड्डा के पिता) ही कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए थे। यूं भी कांग्रेस पार्टी का समूचा नेतृत्व उस समय गैर-किसान नेताओं के हाथों में था। वर्ष 1956 में चौ. देवीलाल संयुक्त पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे और इससे पूर्व 1952 में सर छोटू राम की ज़मींदारा पार्टी के उम्मीदवार को हराकर विधानसभा में चुने गए। चौ. देवीलाल ने एक रोचक प्रसंग का जिक्र किया है कि वे जेल से रिहा होकर हिसार रेलवे स्टेशन के गेस्ट रूम में पहुंचे तो वहां सर छोटू राम से उनकी मुलाकात हो गई। छोटू राम लाहौर जाने की तैयारी में थे। उन्होंने चौ. देवीलाल को बुलाकर समझाने का प्रयास किया कि कांग्रेस अभिजात्य वर्ग की पार्टी है। समूचा नेतृत्व इसी वर्ग का है। हमें सिर्फ कार्यकर्ता और वोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बेवजह अपना वक्त और भविष्य इस पार्टी में बर्बाद मत करो। चौ. देवीलाल उस समय आजादी के आंदोलन के बड़े नेता के रूप में ख्यात हो चुके थे। लेकिन आजादी के बाद भी लंबे समय तक संयुक्त पंजाब की कमान कभी किसान परिवार के नेताओं के हाथ नहीं लगी। सर छोटू राम की दूरदर्शिता इससे साबित हुई। हरियाणा क्षेत्र के साथ हो रहे भेदभाव को उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उठाना शुरू किया, जिसकी परिणति 1966 में पृथक राज्य हरियाणा के अस्तित्व में आने के रूप में हुई।समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया उस समय गैर कांग्रेसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। डॉ. लोहिया उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद कन्नौज से समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव मैदान में थे। चौ. देवीलाल गाड़ियों के काफिले के साथ वहां पहुंचे और सघन चुनाव प्रचार में लग गए। डॉ. लोहिया विजयी रहे। चौधरी देवीलाल ने उन्हें बधाई देते हुए सारे देश में इस मिशन को लेकर भ्रमण करने का आग्रह किया और कहा कि इसमें वे भी उनके सक्रिय साथी की भूमिका में होंगे। इतिहास गवाह है कि 1967 में हरियाणा प्रांत में बनी।

ईशा हत्याकांड में इंसाफ, दरिंदे दारोगा को उम्रकैद

» प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया

कानपुर। दस साल पहले शहर को दहला देने वाले ईशा हत्याकांड में आखिरकार अदालत का बड़ा फैसला आ गया। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ शुचि श्रीवास्तव की कोर्ट ने बुधवार को आरोपी दारोगा ज्ञानेंद्र सिंह को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने माना कि हत्या का जिम्मेदार वही है, जबकि विवेचना में घोर लापरवाही रही।

» **पहली पत्नी छिपाकर रिसेप्शनिस्ट से की थी शादी, बाद में कर दी हत्या**

» **पांच अन्य बरी, विवेचना की खामियों पर अदालत ने जताई नाराजगी**

काकादेव की होटल रिसेप्शनिस्ट ईशा और तत्कालीन मूसा नगर थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र का प्रेम विवाह 2013 में हुआ था। ईशा ने एक बेटी को जन्म भी दिया। बाद में उसे पता चला कि ज्ञानेंद्र पहले से शादीशुदा है। यहीं से विवाद शुरू हुआ। 18 मई 2015 को ज्ञानेंद्र मंदिर ले जाने के बहाने ईशा को घर से ले गया और फिर वह जिंदा वापस नहीं लौटी।

धड़ मिला, सिर नहीं; पुलिस की लापरवाही उजागर

ईशा की मां विनीता सचान ने बेटी के अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई। कुछ दिन बाद पुलिस ने कौशांबी में गंगा किनारे से महिला का धड़ बरामद किया, पहचान टैटू और गहनों से हुई।

लेकिन हत्या के बाद अलग किया गया सिर आज तक नहीं मिल पाया। अदालत ने विवेचक उदय प्रताप सिंह पर गंभीर टिप्पणी की कि उसने दारोगा को बचाने की कोशिश की और सिर बरामद कराने में लापरवाही की। कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।शहर में यह हत्याकांड उस वक्त सनसनी बना था। आरोपी दारोगा हमेशा दावा करता था कि उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि वह कानून जानता है, लेकिन बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर उसका चेहरा पहली बार तनावग्रस्त नजर आया।फैसले के दौरान कोर्ट में मौजूद ईशा की मां विनीता और भाई एश्वर्य सचान पूरी सुनवाई में आंसुओं में डूबे रहे। विनीता ने कहा– मेरी बेटी की हत्या करने वाले को फांसी मिलनी चाहिए थी, हम हाईकोर्ट जाएंगे।

11 साल की बेटी अब नानी और मामा के साथ रह रही है। मां की मौत और पिता की उम्रकैद ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। परिवार ने कहा कि यही बच्ची अब उनके जीने का सहारा है।

सीएम ग्रिड योजना: गुरूदेव चौराहा से चिड़ियाघर तक 44.58 करोड़ से बनेगी सड़क

» **उन्नयन योजना का मेयर प्रमिला पांडेय और स्थानीय विधायक, पार्षद सहित अफसरों ने किया भूमि पूजन**

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना (सीएम-ग्रिड) के तहत शहरवासियों को बेहतर सड़क और आधुनिक सुविधाएं देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बुधवार को महापौर ने विधायक नीलिमा कटियार एवं पार्षद राजकिशोर यादव, धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी और कुन्ती निषाद के साथ गुरूदेव सिनेमा चौराहा से चिड़ियाघर तक 2.75 किमी सड़क के समेकित विकास एवं उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया।इस परियोजना पर 44 करोड़ 58 लाख 58 हजार रुपये की लागत आएगी। कार्यक्रम में मुख्य अभियंता (सिविल) सैय्यद फरीद अख्तर जैदी, अधिशासी अभियंता जोन-6 आर.के. सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। महापौर ने

कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी और लोगों को विश्वस्तरीय सड़क सुविधा मिलेगी। वहीं विधायक नीलिमा कटियार ने इसे शहर के सतत विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया।

परियोजना की खासियतें

- टिकाऊ व्हाइट टॉपिंग सड़क, उन्नत रोड मार्किंग व रिफ्लेक्टिव पैवमेंट
- दृष्टिबाधितों के लिए टैक्टाइल टाइल्स व आधुनिक पेवर ब्लॉक्स
- हरित डिवाइडर, बागवानी और पौधारोपण से पर्यावरण संरक्षण
- अत्याधुनिक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रणाली व यूटिलिटी डक्ट
- ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीट लाइट और हाई-मास्ट लाइट्स
- सार्वजनिक बेंच व स्ट्रीट फर्नीचर

कानपुर नगर निगम

पुलिस थाने का किया घेराव

सिद्धनाथ घाट पर पंडों और डोम में मारपीट, महिलाओं से दुर्व्यवहार का लगा आरोप

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सिद्धनाथ घाट पर पंडों और डोम समुदाय के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद डोम समुदाय ने थाने का घेराव कर हंगामा किया। डोमों ने पंडों पर मारपीट और महिलाओं से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है।

कानपुर में जाजमऊ स्थित सिद्धनाथ घाट पर पंडों और डोमों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद डोम समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव कर हंगामा किया। डोम समुदाय के लोगों का आरोप है कि उनकी कई पीढ़ियां सिद्धनाथ घाट पर अंतिम संस्कार से जुड़े काम करती आ रही हैं,

लेकिन इसके बावजूद यहा के पंडे उनके साथ मारपीट करते हैं।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पंडों ने उनके घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट की है और जान से मारने की धमकी दी है। गुरुवार को इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में फिर से झगड़ा हुआ, जिसके बाद डोम समुदाय के लोग आक्रोशित होकर जाजमऊ थाने पहुंचे और न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

खूंखार रंगदारी कांड: होटल संचालिका के बयान से कांप उठा शहर

» एक आरोपित की हो चुकी मौत, बाकी पांच के खिलाफ वारंट जारी करने की तैयारी

» पांच घंटे में मुकदमा खत्म करने वाले तत्कालीन विवेचक पर विभागीय जांच शुरू

» प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया

कानपुर। साकेत नगर निवासी होटल संचालिका प्रज्ञा त्रिवेदी ने रंगदारी प्रकरण में मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज कराते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2010 में अखिलेश दुबे ने उनसे होटल चलाने के एवज में दो लाख रुपये प्रतिमाह रंगदारी मांगी थी। रुपये न देने पर वह अपने करीबी भूपेश अवस्थी, बेटे रोहित अवस्थी, अजय निगम, अनुज निगम और दो-तीन अज्ञात असलहाधारियों के साथ होटल में घुस आया। सभी ने मिलकर उन्हें लात-घूंसे मारे, गाली-गलौज की और धमकी दी कि यदि समय पर रुपये नहीं दिए तो होटल बंद करा देंगे और परिवार को भी जान से मार देंगे।

प्रज्ञा का कहना है कि आरोपियों ने मारपीट के दौरान न केवल होटल में तोड़फोड़ की बल्कि उन्हें रिश्तेदारों से जबरन 1.20 लाख रुपये दिलवाए। यह रकम भी अखिलेश दुबे और उसके साथियों ने दबाव डालकर अपने कब्जे में ले ली थी। उन्होंने कहा कि अजय निगम की अब मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बाकी आरोपी वर्षों से खुलेआम घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे घटनाक्रम को उस समय के प्रभावशाली लोगों ने दबा दिया और उन्हें न्याय से वंचित कर दिया। अब 14 साल बाद उन्हें उम्मीद जगी है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और कानून के सामने सच सामने आएगा।

पुलिसिया जांच पर उठे सवाल

पीड़िता के अनुसार, 2011 में जूही थाने में दर्ज हुए मुकदमे की विवेचना तत्कालीन उप निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने की थी। लेकिन जांच इतनी जल्दबाजी में की गई कि पांच घंटे के भीतर ही अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। इसमें प्रमुख नामों को जानबूझकर हटा दिया गया और मामले को कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई। प्रज्ञा ने आरोप लगाया कि विवेचक ने उनके बयान तक दर्ज नहीं किए और सिर्फ प्रभावशाली लोगों के बयान दर्ज करके रिपोर्ट को बंद कर दिया। यही वजह रही कि इतने गंभीर अपराध के बावजूद आरोपी बिना किसी सजा के बच निकले।अब पीड़िता की गुहार पर कोर्ट ने पुनर्विवेचना के आदेश दिए। आठ सितंबर 2025 को कोर्ट ने साफ कहा कि मामले की जांच एसीपी स्तर के अधिकारी से कराई जाए और तत्कालीन विवेचक पर विभागीय जांच शुरू की जाए। पुलिस आयुक्त ने इसके बाद प्रकरण की पुनर्विवेचना एसआइटी सदस्य एसीपी नौबस्ता चित्रांशु गौतम को सौंपी है। वहीं तत्कालीन विवेचक तिवारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जांच एसीपी बाबूपुरवा दिलीप सिंह को दी गई है। शुक्रवार रात पुलिस की टीम प्रज्ञा के घर पहुंची और उनके बयान दर्ज किए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मजिस्ट्रेटी बयान के आधार पर अब नामजद आरोपितों के खिलाफ वारंट जारी किए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी।

काशी ज्वैलर्स ने पेश किया नया डायमंड ज्वैलरी ब्रांड 'शी बाय काशी'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 26 सितंबर को होगा भव्य शुभारंभ

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। भारत के प्रतिष्ठित ज्वैलरी ब्रांड काशी ज्वैलर्स ने अपनी 70 वर्षों की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए नया डायमंड ज्वैलरी ब्रांड 'शी बाय काशी' लॉन्च करने की घोषणा की है। इस ब्रांड का भव्य शुभारंभ 26 सितंबर को स्वरूपनगर स्थित काशी ज्वैलर्स के शोरूम में किया जाएगा। यह जानकारी 'शी बाय काशी' के संस्थापक एवं निदेशक श्रेयांश कपूर और संस्थापिका एवं डिज़ाइनर देविका कपूर ने साझा की।

काशी ज्वैलर्स की सात दशकों से प्रतिष्ठा परंपरा, गुणवत्ता और ग्राहकों के विश्वास के आधार पर रही है। अब उसी विरासत को नए आयाम देते हुए 'शी बाय काशी' एक ऐसा संग्रह पेश करता है जो हर महिला के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को समर्पित है।

ब्रांड का उद्देश्य आधुनिक महिला की पहचान, उसकी आत्म-अभिव्यक्ति और खूबसूरती को उजागर करना है। 'शी बाय काशी' के डिज़ाइन इस सोच पर आधारित हैं कि गहने केवल खास मौकों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं की रोज़मर्रा की जिंदगी और उनके सपनों का हिस्सा बनने चाहिए। प्रत्येक आभूषण प्राकृतिक हीरों से तैयार किया गया है, जो उत्कृष्टता और कालातीत सुंदरता का प्रतीक है।4,999 से शुरू होने वाली कीमतों के साथ, यह संग्रह हर महिला की पहुंच में है। श्रेयांश कपूर ने कहा, दशकों से काशी ज्वैलर्स अपने ग्राहकों की खुशियों का हिस्सा रहा है। 'शी बाय काशी' के माध्यम से हम हर दिन को खास बनाना चाहते हैं। यह केवल गहने नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अपनी पहचान जीने की कला हैं।

संस्थापिका और डिज़ाइनर देविका कपूर ने बताया, एक महिला डिज़ाइनर के रूप में, मैंने यह संग्रह हर महिला की व्यक्तिगत यात्रा का साथी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया है। हर टुकड़ा हल्का, प्रामाणिक और उसकी अपनी कहानी कहने वाला है।

'शी बाय काशी' केवल एक ज्वैलरी ब्रांड नहीं, बल्कि महिलाओं के हर रूप, हर दिन और हर सपनों का सम्मान करने वाली सोच का प्रतीक है। यह संग्रह लालित्य को आत्म-अभिव्यक्ति और सौंदर्य के सहज मिश्रण के रूप में परिभाषित करता है।

विजय नगर चौराहा स्टेशन के लिए रखा गया पहला डबल टी-गर्डर

कानपुर। मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-2 के अंतर्गत बन रहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी-बर्रा-8 एलिवेटेड सेक्शन का निर्माण कार्य हो रहा है। इस कड़ी में मंगलवार को लगभग 4.50 किमी लंबे सेक्शन के लिए डबल टी-गर्डर्स रखने का काम भी आरंभ कर दिया गया ।पहले इस सेक्शन के विजय नगर चौराहा स्टेशन के लिए डबल-टी गर्डर्स को रखा गया।कानपुर मेट्रो की एलिवेटेड अवसंरचना में स्टेशनों के कॉनकोर्स (एलिवेटेड स्टेशन का पहला तल) को आधार देने के लिए डबल टी-गर्डर्स का प्रयोग होता है। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा, कि कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी - बर्रा-8 एलिवेटेड सेक्शन का सिविल निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।हमने इस सेक्शन के तीन-चौथाई से अधिक पाइलिंग, पाइल कैप और पियर निर्माण कार्य पूरे कर लिए हैं। पियर-कैप्स का 63 प्रतिशत से अधिक इरेक्शन कार्य भी पूरा हो चुका है। अब उक्त सेक्शन के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों के लिए डबल टी-गर्डर्स के इरेक्शन का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

सस्ता बाजार-खुशहाल त्यौहार जीएसटी राहत से उमंग में उपभोक्ता

दुकानदारों को नए रेट चस्पा करने का निर्देश, 'धन्यवाद मोदी सरकार' के लगे नारे

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो,

कानपुर देहात। जीएसटी बचत उत्सव के तहत केंद्र और प्रदेश सरकार पूरे देश में जनता को जागरूक करने का अभियान चला रही है। इसी क्रम में बुधवार को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद रनिया पहुंचे। यहां पड़ाव बाजार में व्यापारियों से मुलाकात कर उन्होंने घटे हुए जीएसटी दरों से मिलने वाले लाभ पर चर्चा की। मंत्री ने दुकानों के बाहर पंपलेट चिपकाए और लोगों से अपील की कि वे ग्राहकों को सस्ते दामों का सीधा फायदा दें।इसके बाद रनिया पड़ाव से किसरवल रोड तिराहे तक पैदल यात्रा निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने नारे लगाए घटी जीएसटी, मिला उपहार धन्यवाद मोदी सरकार। मौके

» रनिया में व्यापारियों संग पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद

पर कैबिनेट मंत्री ने उपायुक्त आयकर अमित अग्रवाल से कहा कि कुछ दुकानदार अभी भी पुराने रेट पर सामान बेच रहे हैं, इसलिए दुकानों के बाहर नए रेट तत्काल चस्पा कराए जाएं।मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए दीपावली से पहले किसी तोहफे से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की तकलीफों को देखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है। इस मौके पर उपायुक्त आयकर अमित अग्रवाल, अतिरिक्त एसडीएम अवनीश कुमार सिंह, नायब

तहसीलदार रविंद्र नाथ मिश्रा, मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भाई की मौत का ग़म बना जानलेवा मजदूर ने लगाई फांसी

» सुबह घर से निकला, खेतों में पेड़ पर झूलता मिला शव

» पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल, पुलिस ने भेजा पोस्टमार्टम

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। थाना रनियां क्षेत्र के चिराना गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने एक युवक को पेड़ से फांसी पर लटका देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

चिराना गांव निवासी महेंद्र सिंह (45) पुत्र तेज सिंह, रनियां की एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी करता था। मृतक के साले विनोद सिंह के मुताबिक, महेंद्र के बड़े भाई की करीब एक सप्ताह पहले मौत हो गई थी। इसके बाद से वह गुमसुम और मायूस रहने लगे थे। बुधवार की भोर वह अचानक घर से निकल गए और लगभग 500 मीटर दूर खेतों के पास स्थित जामुन के पेड़ से रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।घटना की खबर फैलते ही गांव में मातम छा गया। मृतक की पत्नी नीरज देवी और बेटे कुलदीप सिंह व सूरज सिंह का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। थानाध्यक्ष एसएन सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया अधिक शराब पीने और भाई की मौत के ग़म में युवक ने यह कदम उठाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच की जा रही है।

सड़क निर्माण का अधूरा वादा, बदहाल हालात पर सर्वे शुरू

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। सरवनखेड़ा में करीब 25 साल से सेरूवा-लोहारी मार्ग का अधूरा निर्माण आखिरकार प्रशासन की नजर में आ ही गया। बुधवार को जिला पंचायत की चार सदस्यीय टीम ने गांव पहुंचकर सड़क का सर्वे किया।

» ग्रामीण बोले आधी सड़क बनी, आधी रह गई खस्ताहाल

» अभिलेखों में दर्ज न होने से विभागों ने झाड़ा पल्ला

टीम ने लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की नापजोख के साथ ग्रामीणों से भी जानकारी ली। लोगों ने बताया कि सड़क की करीब दो किलोमीटर लंबाई में सिर्फ 600 मीटर हिस्सा करीब 25 साल पहले बनाया गया था, बाकी हिस्सा आज तक अधूरा है।ग्रामीण विनय तिवारी, जयंत सिंह और कमलेश पासवान ने टीम को बताया कि जब कानपुर शहर और देहात एक ही जिला था, तब जिला पंचायत ने 600 मीटर सड़क बनाई थी। उसके बाद लोक निर्माण विभाग और मंडी समिति दोनों ने इस सड़क को अपने विभाग की न मानकर मरम्मत तक से किनारा कर लिया। नतीजा यह है कि दो किलोमीटर की सड़क का अधिकांश हिस्सा जर्जर हाल में पड़ा है।ग्राम प्रधान मंगल सिंह परिहार के अनुरोध पर जिला पंचायत ने यह सर्वे कराया। मौके पर पहुंचे अवर अभियंता राहुल सिंह व जेई राहुल राजभर ने पूरी नापजोख कर अभिलेखों की कमी की पुष्टि की। टीम में सौरभ और दीपक भी शामिल रहे। अवर अभियंता ने बताया कि सड़क का कोई बोर्ड या रिकॉर्ड विभागीय अभिलेख में दर्ज नहीं मिला, लेकिन ग्रामीणों के बयान के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को सौंपी जाएगी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादक: अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

कान्हा गौशाला में आधुनिक प्रबंधन और उत्तम सुविधाओं का इंतजाम

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम द्वारा संचालित कान्हा गौशाला, किशनपुर ने अपनी आधुनिक व्यवस्थाओं और उत्तम सुविधाओं के माध्यम से प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय का ध्यान आकर्षित किया। मंत्री ने गौशाला का औचक निरीक्षण किया और गौवंश के बेहतर खान-पान, स्वास्थ्य और प्रबंधन की सराहना की।

» मंत्री ने विजिटर्स डायरी में लिखा गाय माता न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं उच्च कोटि की हैं।

» कानपुर महानगर के प्रभारी मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने किया निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने सबसे पहले गौ-पूजन किया और गौवंश को गुड़ व केला खिलाया। इसके बाद गौशाला की ग्रीन बेल्ट में पौधारोपण किया गया।

मंत्री ने गौ-उत्पादों जैसे गौ-मय दीपक, गौ-काष्ठ, मूर्ति और वर्मीकम्पोस्ट आदि का अवलोकन किया। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि गौशाला उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ब्रुस्ह प्रमाणित गौशाला है, जहाँ वर्तमान में 6200 गौवंश संरक्षित हैं और उनके खान-पान के लिए पर्याप्त भूसा, चोकर और हराचारा उपलब्ध है।

मंत्री ने विजिटर्स डायरी में लिखा -गाय माता न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं उच्च कोटि की हैं। इसके लिए जिम्मेदार कर्मियों को साधुवाद।

कान्हा गौशाला की व्यवस्थाएं और वहां उपलब्ध सुविधाएं यह दर्शाती हैं कि नगर निगम पशु संरक्षण के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रहा है।

एबीसी सेंटर, किशनपुर का भी किया निरीक्षण

मंत्री श्री उपाध्याय ने एबीसी सेंटर, किशनपुर का भी निरीक्षण किया। यहाँ वेटनरी सर्जनों द्वारा प्रतिदिन लगभग 40 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। मंत्री ने नगर निगम की इस पहल की सराहना की और कहा कि यह पशु कल्याण और मानव समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रेम प्रसंग के चलतं युवती की हत्या, झाड़ियों में मिला शव

» शिवली कोतवाली के मैथा लालपुर गांव का मामला

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कक्कानपुर देहात।देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के मैथा लालपुर गांव में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। गांव के बाहर झाड़ियों में युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सरमन की पुत्री शांति के रूप में हुई है।प्राथमिक जांच में पुलिस को मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने की आशंका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि विवाद के चलते शांति की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

फिलहाल पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के पीछे की असल वजह स्पष्ट हो पाएगी। इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

रूरा-अकबरपुर सीएनजी बस सेवा ठप्प, 5 हजार यात्रियों की परेशानियाँ बढ़ीं

» बसों के बंद होने से यात्रियों और फैक्ट्री कर्मचारियों का दैनिक जीवन प्रभावित

» मनमानी किराया और डिपो की अनदेखी यात्रियों को कर रही परेशान

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। रूरा-अकबरपुर से कानपुर के बीच चलने वाली सीएनजी बस सेवा ठप्प हो गई है। पहले 28 बसें 20 मिनट के अंतराल पर रूरा से कानपुर जाती थीं, लेकिन बसों के कंडम होने के कारण धीरे-धीरे संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसका असर करीब 5,000 यात्रियों पर पड़ रहा है। इनमें फैक्ट्री कामगार, छात्र और माती मुख्यालय आने-जाने वाले आमजन शामिल हैं।

कई लोग अब मनमानी ऑटो और ई-रिक्शा का सहारा लेने को मजबूर हैं ।यात्री अब रूरा-अकबरपुर दूरी के लिए ऑटो और ई-रिक्शा से ?30 प्रति सवारी चुकाने को मजबूर हैं, जबकि पहले ?20 में यात्रा होती थी। माती डिपो में 30 बसों के बावजूद डेढ़ दर्जन बसें खड़ी हैं

और इन्हें मुख्य मार्गों पर नहीं चलाया जा रहा। इससे ग्रामीण और शटल बस सेवा के इंतजार में यात्री परेशान हैं। डिपो अधिकारियों की लापरवाही के कारण अब तक राहत नहीं मिली।

यात्रियों का कहना है कि परिवहन विभाग सिर्फ राजस्व की चिंता कर रहा है और आम जनता की यात्रा को नजरअंदाज कर रहा है।

पुलिस ने घेरा तो प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारी

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

बुलंदशहर। यूपी के बुलंदशहर जिले के डिबाई क्षेत्र में बृहस्पतिवार को एक युवक ने अपनी प्रेमिका की कथित रूप से गोली मारकर हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि डिबाई थाना क्षेत्र के सराय किशनचंद मुहल्ले में आज तड़के करीब साढ़े तीन बजे एक मकान में प्रिंस (25) और उसकी 15 वर्षीय कथित प्रेमिका दीया के शव संदिग्ध हालात में पाये गये।

उन्होंने बताया कि प्रिंस और दीया मुजफ्फरनगर से आये थे। इस सिलसिले में मुजफ्फरनगर के छपार थाने में प्रिंस के खिलाफ नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। वे दोनों बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र स्थित सराय किशनचंद मुहल्ले में नरेन्द्र कुमार के मकान में किराये पर रह रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर मुजफ्फरनगर के छपार थाने की पुलिस लड़की को मुक्त कराने के लिये प्रिंस के किराये के मकान पर पहुंची थी। सूत्रों ने बताया कि पुलिस के साथ प्रिंस का फूफा भी था और उसने उससे दरवाजा खोलने के लिये कहा था, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। कुछ ही देर बाद बगल में रहने वाले लायक सिंह नामक व्यक्ति की छत पर गोली चलने की आवाज सुनायी दी।

सूत्रों के अनुसार, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रिंस और दीया के खून से लथपथ शव बरामद किये। दोनों के सिर में गोली लगी थी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्ट्या ऐसा लगाते है कि

लड़के ने लड़की को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली, जिससे दोनों की मौत हो गयी। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गये हैं।

बेसिक शिक्षा निदेशक पर बीजेपी विधायक ने लगाया रिश्वत लेने का आरोप

विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, जांच की मांग

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कासगंज/लखनऊ ।कासगंज से बीजेपी विधायक देवेन्द्र सिंह राजपूत ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। विधायक का आरोप है कि उनके विद्यालय का वर्षों से रुका हुआ वेतन भुगतान कराने के नाम पर निदेशक ने 25 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की ।विधायक राजपूत ने पत्र में उल्लेख किया है कि कासगंज जनपद के बिलराम स्थित सरदार भगत सिंह जूनियर हाई स्कूल में नियमित पठन-पाठन का कार्य चल रहा है। बावजूद इसके मार्च 2011 से विद्यालय का वेतन भुगतान नहीं किया गया। जबकि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ खंडपीठ ने तीन माह के भीतर एरियर भुगतान करने का आदेश दिया था।

पत्र के अनुसार, निदेशक प्रताप सिंह बघेल और बाबू अजय शंकर ने 25 लाख रुपये की मांग की थी। आरोप है कि 10 लाख रुपये पहले ही वसूले जा चुके हैं, लेकिन शेष राशि के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है और विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी जा रही है।

विधायक राजपूत ने मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है।

यह मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस गंभीर आरोप पर क्या रुख अपनाती है।

सोचो स्वास्थ्य, सोचो फार्मासिस्ट के माध्यम से जागरूकता का संदेश

अयोध्या। विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रेस क्लब में संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुशील तिवारी ने कहा कि फार्मासिस्ट केवल दवाइयाँ देने वाले नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अहम स्तंभ हैं। विशिष्ट अतिथि राकेश यादव ने फार्मासिस्टों की भूमिका को दवाओं के सुरक्षित उपयोग और जनजागरूकता से जोड़ा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने की और महासचिव अभिषेक जायसवाल ने फार्मासिस्टों की प्रतिबद्धता को समाज के लिए सराहनीय बताया। इस अवसर पर जिले के दर्जनों फार्मासिस्ट मौजूद रहे।

उन्नाव में होमगार्ड के घर बड़ी चोरी, तीस लाख की ज्वैलरी व नकदी पार

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

उन्नाव। माखी थाना क्षेत्र के कोरारी कलां गांव में बुधवार की रात चोरों ने पुलिस विभाग में तैनात एक होमगार्ड के घर पर धावा बोलकर लाखों का माल पार कर दिया। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

गांव निवासी सुनील कुमार सिंह पुत्र स्व. रामऔतार सिंह, जो कानपुर यातायात विभाग में होमगार्ड के पद पर तैनात हैं, ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार रात ड्यूटी से लौटने के बाद वे परिवार के साथ खाना खाकर घर के बाहरी बरामदे में सो गए थे। सुबह जब घर के अंदर गए तो कमरे का ताला टूटा मिला और सारा सामान बिखरा पड़ा था।

जांच में सामने आया कि चोर मकान के पीछे से छत के रास्ते भीतर दाखिल हुए। चादर की गांठ बनाकर एक चोर को आंगन में उतारा गया, जिसने भीतर से दरवाजा खोलकर साथियों को अंदर बुला लिया। इसके बाद चोरों ने अलमारी, बक्सा और बेड खंगालते हुए करीब दो लाख रुपये नकद और तीस लाख की ज्वैलरी पार कर दी।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। थाना प्रभारी योगेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही चोरों का सुराग लगाकर कार्रवाई की जाएगी।

अयोध्या में फैला जमीन माफियाओं का बड़ा जाल

» एसएसपी की सख्ती से खुलने लगे हैं राज

74 लाख की ठगी का बड़ा मामला, तीन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच जारी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।अयोध्या में जमीन की खरीद-फरोख्त अब आम लोगों के लिए जाल और धोखे का खेल बन गई है। आए दिन सुनने में आता है कि फर्जी कागजों, दो नंबर के एग्रीमेंट और विवादित प्लॉट दिखाकर भोले-भाले लोगों से लाखों-करोड़ों रुपये ऐंठ लिए जाते हैं। ताजा मामला रानोपाली का है, जहां जमीन माफियाओं ने एक व्यक्ति से 74 लाख रुपये की ठगी कर ली।शहर के पहाड़गंज निवासी पवन कुमार तिवारी को पहले जमीन दिखाकर मात्र 10 लाख रुपये में सौदा तय किया गया।

छह लाख रुपये देकर एग्रीमेंट भी कराया गया, लेकिन जब बैनामा कराने का समय आया तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी। बाद में पवन को पता चला कि जमीन पर पहले से ही दो न्यायालयों से स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) जारी थे। इसके बावजूद आरोपियों ने दबाव डालकर विवाद खत्म होने पर अधिक रुपये मांगने शुरू कर दिए।

विश्वास और मजबूरी के बीच पवन कुमार ने अपने परिचितों के जरिए कुल 74 लाख रुपये हर्ष कुमार पांडेय, संजय कुमार और सत्यसेन सिंह को थमा दिए।

लेकिन धोखाधड़ी यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपियों ने 14 अक्टूबर, 2024 को वही जमीन किसी और के नाम बैनामा करा दी। जब पवन ने सवाल किया तो उसे मारपीट कर भगा दिया गया।

पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। नगर कोतवाली में हर्ष कुमार पांडेय, संजय कुमार और सत्यसेन सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। इंस्पेक्टर अश्विनी पांडेय ने बताया कि मामले की जांच जारी है और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

भूमाफियाओं का ट्रैक रिकॉर्ड

-2019- अयोध्या के देवकाली क्षेत्र में एक परिवार से 42 लाख रुपये लेकर फर्जी रजिस्ट्री कराई गई थी। मामला कोर्ट में अटका, लेकिन आरोपियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।

-2021- कैंट क्षेत्र में दो अलग-अलग लोगों को एक ही प्लॉट बेचने का मामला सामने आया। पीड़ितों ने थाने से लेकर एसएसपी तक गुहार लगाई।

-2023- दरियाबाद रोड पर सरकारी भूमि को निजी बता कर बैनामा कर दिया गया। बाद में राजस्व टीम की जांच में पूरा खेल खुला।

-2024- सहादतगंज में एक कारोबारी से 1.10 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सुर्खियों में रहा, जिसमें आरोपियों ने कोर्ट स्टे की जानकारी छिपाकर सौदा कराया था। यह रिकॉर्ड बताता है कि अयोध्या में भूमाफियाओं का नेटवर्क कितना मजबूत और संगठित है। हर साल कई पीड़ित न्याय के लिए चक्कर काटते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा मामलों में ही पुलिस-प्रशासन कार्रवाई करता है।अयोध्या में जमीन के सौदों पर माफियाओं की पकड़ नई नहीं है। आए दिन विवादित जमीनों के नाम पर फर्जी एग्रीमेंट, डबल बैनामा और कोर्ट में झूठे दावों का खेल चलता रहा है। इस बार एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने तत्परता दिखाकर न केवल पीड़ित की सुनवाई की, बल्कि बड़े पैमाने पर सक्रिय जमीन माफियाओं को कड़ा संदेश भी दिया है।

स्वराज इंडिया का सवाल

-आखिर क्यों जमीन रजिस्ट्रेशन और बैनामा से पहले पूरी जांच नहीं होती?
-राजस्व और रजिस्ट्री विभाग की चुप्पी में कौन-कौन शामिल है?
-जब हर बड़े सौदे में दलाल और जमीन माफिया शामिल रहते हैं तो प्रशासन अब तक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया?

अयोध्या की पवित्र भूमि पर जमीन माफियाओं का यह कारोबार सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और आस्था दोनों के लिए चुनौती है। एसएसपी की कार्रवाई ने पीड़ितों को राहत की किरण जरूर दिखाई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब प्रशासन इस गोरखधंधे को जड़ से खत्म करने की हिम्मत दिखाएगा?

फर्जी चकबन्दी लेखपाल का 25 साल बाद खुला घोटाला

» सीजेएम कोर्ट ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। चकबंदी विभाग में फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। फर्जी चकबंदी लेखपाल बने शिवबरन वर्मा के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने नगर कोतवाली को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला 1998-99 का है, लेकिन अब जाकर इसकी परतें खुल रही हैं।

बता दे कि शिवबरन वर्मा ने कूट रचित (फर्जी) दस्तावेज बनवाकर मथुरा बंदोबस्त अधिकारी के कार्यालय से अंबेडकरनगर-फैजाबाद कार्यालय में ट्रांसफर करा लिया।

इतना ही नहीं, मथुरा से फर्जी लेटर पर रिलीव होकर फैजाबाद में आकर ज्वाइन भी कर लिया।

करीब एक साल तक वह फर्जी चकबंदी लेखपाल

बनकर वेतन उठाता रहा। मामला पकड़ में आने के बाद शिकायत अदालत पहुंची।

वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने पूरे मामले की पैरवी की, जिसके बाद कोर्ट ने अब शिवबरन वर्मा पर धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

जनता के सवाल....

-आखिर 25 साल तक इस फर्जीवाड़े की फाइलें दबाकर किसने रखीं?
-चकबंदी विभाग में बिना सत्यापन किए कैसे किसी को नियुक्ति और वेतन जारी होता रहा?
-क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का खेल था या विभागीय मिलीभगत की बड़ी साजिश?

अयोध्या के धन्नीपुर मस्जिद को नकारते विनय कटियार

- » विनय कटियार कहते हैं कि अयोध्या में मुसलमानों का कोई काम नहीं
- » राम नगरी में केवल मंदिर बनेगा, मस्जिद का सवाल ही नहीं कटियार का बयान
- » सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मस्जिद का नक्शा अब तक फंसा, प्राधिकरण ने लौटाया आवेदन
- » 2027 चुनाव से पहले ध्रुवीकरण का नया एजेंडा या अयोध्या की शांति पर नया संकट?

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या।राममंदिर आंदोलन के बड़े चेहरा और बीजेपी के फायरब्रांड नेता विनय कटियार ने धन्नीपुर मस्जिद को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने अयोध्या का राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गरमा दिया है। कटियार ने साफ कहा कि धन्नीपुर में कोई मस्जिद नहीं बनने वाली, मैं धन्नीपुर मस्जिद को जानता ही नहीं। यही नहीं, उन्होंने अयोध्या में रह रहे मुसलमानों को शहर छोड़ने की सलाह देते हुए कहा कि भगवान राम की नगरी में मुसलमानों का कोई काम नहीं, उन्हें सरयू पार चले जाना चाहिए या गोंडा-बस्ती जाकर बस जाना चाहिए। कटियार के इस बयान ने अयोध्या की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। जहां हिंदुत्व समर्थक उनके सुर में सुर मिला रहे हैं, वहीं सेक्युलर और विपक्षी दल इसे सांप्रदायिक राजनीति करार देकर हमला बोल रहे हैं।

क्या नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नकारने लगे हैं?
क्या प्रशासन ऐसे बयानों पर कार्रवाई करेगा या चुप्पी साधे रहेगा?
क्या धन्नीपुर मस्जिद का निर्माण कभी जमीन पर उतर पाएगा या यह राजनीति का स्थायी मुद्दा बन चुका है?

बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में श्रीराम जन्मभूमि विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष को पाँच एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया था। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के धन्नीपुर गांव में पांच एकड़ भूमि आवंटित की।

2022 में मस्जिद निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया शुरू भी हुई, लेकिन आवश्यक दस्तावेज पूरे न होने के कारण आवेदन निरस्त कर दिया गया। अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक मुस्लिम पक्ष को अब नए सिरे से आवेदन करना होगा।

सभी शुल्क दोबारा जमा करने होंगे। मस्जिद निर्माण के लिए विभागीय एनओसी हासिल करनी होगी। वैध दस्तावेज़ों के साथ ही नक्शा स्वीकृत हो पाएगा। यानी फिलहाल धन्नीपुर मस्जिद का मामला अब भी कागजों और प्रक्रियाओं में ही अटका हुआ है।

बीजेपी का एजेंडा होगा कि राममंदिर निर्माण के बाद हिंदुत्व की राजनीति को जीवित रखने के लिए अब धन्नीपुर मस्जिद बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। कटियार का बयान इसी एजेंडे को धार देने की कोशिश है। जबकि विपक्ष की रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल इसे अल्पसंख्यकों को साधने के लिए भुनाने की कोशिश करेंगे। वे बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाएंगे।

2027 यूपी चुनाव पर असर

अयोध्या और पूर्वांचल में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है।बीजेपी के लिए यह मुद्दा राममंदिर के बाद एक नया नैरेटिव गढ़ने का काम करेगा।

विपक्ष इसे संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना बताकर मुस्लिम वोटों को समेटने की कोशिश करेगा। अयोध्या में मस्जिद निर्माण का ठप होना और नेताओं के विवादित बयान, दोनों मिलकर आने वाले चुनावी समीकरणों को गहराई से प्रभावित करेंगे।

दलित नेता सांसद चंद्रशेखर आजाद की बढ़ेंगी मुश्किलें!

यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी ने दी आत्महत्या की धमकी

» स्वराज इंडिया ब्यूरो।

नयी दिल्ली। भारत निवासी और वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड में रह रही पीएचडी शोधार्थी रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया मंच (एक्स) पर भारतीय सांसद और भीम आर्मी/आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद पर यौन और भावनात्मक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं।

ख़बरों के अनुसार, रोहिणी ने बुधवार दोपहर लगभग 2 बजे आत्महत्या की धमकी देते हुए लगातार तीन पोस्ट किए। इनमें उन्होंने लिखा कि उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और पीएमओ को टैग करते हुए यह भी कहा कि मेरी लाश भी भारत वापस मत लाना। किसी ने नहीं सुनी मेरी।

रोहिणी ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने उन्हें धोखे में लाकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उनका शोषण किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि निजी सामग्री के सार्वजनिक किए जाने की धमकी दी गई। रोहिणी का कहना है कि उन्होंने पहले भी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक एजेंसियों की निष्क्रियता तथा राजनीतिक दबाव के कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई।

महिला आयोग की प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश महिला आयोग और कुछ स्थानीय प्रतिनिधियों ने कहा है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई होगी। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि दोषी पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब तक किसी स्वतंत्र सरकारी एजेंसी की ओर से न तो प्राथमिकी दर्ज होने की और न ही किसी ठोस कदम की पुष्टि हुई है।

प्रकाशित रिपोर्टों में कहा गया है कि पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई नहीं हो सकी। कुछ समाचारों के अनुसार, उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी पत्र लिखा था और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग किया था। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक किसी प्राथमिकी या कानूनी प्रगति की सार्वजनिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित नेताओं पर लगे आरोप राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होते हैं। विरोधी दल और मीडिया ऐसे मामलों को तुरंत उठाते हैं, जिससे नेता की नैतिक छवि प्रभावित होती है। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे दलित नेता के खिलाफ लगे आरोप उनकी छवि को सीधा झटका देते हैं। हालांकि जब तक अदालत या पुलिस पुष्टि नहीं करती, आरोपों को केवल आरोप ही माना जा सकता है।

दलित नेतृत्व और राजनीति पर असर

भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से चंद्रशेखर दलित राजनीति का एक नया केंद्र बने। ऐसे में उन पर लगे आरोप समुदाय के भीतर नाराज़गी और समर्थन दोनों को जन्म दे सकते हैं। विरोधी राजनीतिक दल इस मुद्दे का इस्तेमाल मतभेद पैदा करने के लिए कर सकते हैं।

रोहिणी के ट्वीट और आत्महत्या की धमकी यह दर्शाते हैं कि प्रभावशाली व्यक्तियों पर आरोप लगाने वालों को न्याय पाना कठिन होता है। ऐसे मामलों में मीडिया, महिला आयोग और नागरिक संस्थाओं की भूमिका बेहद अहम हो जाती है ताकि पीड़ितों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित हो सके।

फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टिंग में केवल आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता ने सोशल मीडिया और विभिन्न संस्थाओं को शिकायत भेजी है, लेकिन अब तक अदालत या पुलिस की ओर से कोई निर्णायक कार्रवाई सामने नहीं आई है। पत्रकारिता के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि खबर में इसे केवल आरोप या दावा के रूप में ही प्रस्तुत किया जाए।

बहराइच का यह मामला उड़ा देगा होश

मदरसे पर छापा, शौचालय में बंद मिलीं 40 नाबालिग

» सहमी-डरी सभी बच्चियों की उम्र नौ से चौदह वर्ष।

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की पयागपुर तहसील क्षेत्र की एक तीन मंजिला इमारत में संचालित कथित अवैध मदरसे में निरीक्षण के दौरान उसके शौचालय में 40 नाबालिग बच्चियां संदिग्ध हालात में बंद पायी गयीं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसे को तत्काल बंद कराने तथा बच्चियों को सुरक्षित उनके घर भिजवाने के निर्देश दिए हैं। पयागपुर तहसील के उप जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे ने बृहस्पतिवार को मीडिया को बताया कि पयागपुर तहसील के पहलवारा गांव में तीन मंजिला भवन में अवैध मदरसा संचालित होने की शिकायत पर वह अपनी टीम के साथ बुधवार को उसका निरीक्षण करने गये थे।

उन्होंने बताया, मदरसा संचालकों ने पहले तो हमें ऊपर जाने से रोका। पुलिस बल की मौजूदगी में जब हमने मदरसे में प्रवेश किया तो छत पर बने शौचालय का दरवाजा बंद मिला। महिला पुलिस बल ने दरवाजा खुलवाया तो शौचालय में छिपी 40 बच्चियां एक-एक कर बाहर आने लगीं। सभी की उम्र नौ से 14 वर्ष के बीच है। बच्चियां सहमी हुई थीं और कुछ बता नहीं पा रही थीं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद खालिद ने बताया कि बच्चियां शौचालय में क्यों बंद थीं, इस सवाल पर मदरसे की शिक्षिका तकसीम फातिमा ने बताया कि वे अचानक हुए निरीक्षक के चलते मची अफरातफरी से डरकर खुद ही शौचालय में जाकर छुप गयी थीं।

मदरसे को बंद करने के दिए गये निर्देश

खालिद ने बताया मदरसे के अभिलेखों की जांच शुरू कर दी गयी है। फिलहाल मदरसे को बंद करने के निर्देश दिए गये हैं। मदरसा प्रबंधन से बच्चियों को सुरक्षित उनके घरों तक भिजवाने के लिए कहा गया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) रामानंद प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि किसी बच्चे के अभिभावक, उप जिलाधिकारी या अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ओर से अभी तक प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कोई तहरीर नहीं मिली है। उनके अनुसार, अगर कोई शिकायत मिलेगी तो कार्यवाही की जाएगी।

खाद मांग रहे किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज पांच को लगी गंभीर चोट!

पुलिस ने कहा- कोई जख्मी नहीं हुआ, सिर्फ जाम खुलवाया

» विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

महोबा। उत्तर प्रदेश में महोबा जिले के कबरई क्षेत्र में खाद वितरण में की जा रही कथित धांधली के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किये किसानों पर पुलिस द्वारा किये गए बर्बर लाठी चार्ज में पांच किसान जख्मी हो गये। जिले के किसान संगठनों ने घटना का विरोध किया है और खाद के लिए जिले में बड़ा आंदोलन छेड़ने की धमकी दी है। कबरई की सहकारी समिति नंबर 2 में सुबह खाद वितरण में चहेतो को वरीयता देने और टोकन वितरण में धाँधली पर भड़के किसानों की भारी भीड़ ने नारेबाजी करते हुए हँगामा किया और इसके विरोध में कानपुर- सागर राष्ट्रीय राजमार्ग में जाम लगा दिया। वे नियमानुसार सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराये जाने की मांग कर रहे थे।

आरोप था कि सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए पुलिस कर्मी भी टोकन दिलाने के लिए वसूली कर रहे है। घर की महिलाओं और बच्चों के साथ सड़क पर किसानों के धरना शुरू कर देने से राज मार्ग में आवाजाही ठप हो गयी। सड़क के दोनों और बड़ी संख्या में वाहन फंस कर खडे हो गए। जिससे यात्रियों के समक्ष भारी परेशानी खड़ी हो गयी। पुलिस उप अधीक्षक एके सिंह ने बताया कि आंदोलनकारियों के साथ भीड़ में मौजूद कतिपय उपद्रवी तत्वों का बवाल करीब एक घंटे तक चलता रहा, जिससे स्थिति बिगड़ने लगी। पुलिस ने तब किसानों को समझा बुझा कर जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन उनके न मानने और हालात काबू में न होते देख पुलिस को आखिरकार लाठी पटक कर उपद्रवियों को खदेड़ना पड़ा और सड़क को जाम से मुक्त कराया गया। भगदड़ में कुछ लोगों के चोटिल होने की बात कही जा रही है। लेकिन कही किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।

सपा में शामिल हुए अपना दल और बसपा के कई बड़े नेता

2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने चला बड़ा दांव

» लखनऊ, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी (सपा) इस बार पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी न केवल धरातल पर संगठन को मजबूत कर रही है, बल्कि लगातार दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने की कवायद भी तेज कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है।

इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, लाल जी वर्मा ने शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत किया और उन्हें पार्टी की विचारधारा से परिचित कराया। इस दौरान मेंहदी में तलवार पुस्तक का विमोचन भी किया गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही किसानों, मजदूरों, नौजवानों और पिछड़ों की सच्ची आवाज उठाती रही है। भाजपा सरकार ने पिछले नौ वर्षों में सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है।

कार्यक्रम में शामिल हुए नेताओं ने भी कहा कि उन्होंने जनता की समस्याओं और जमीनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सपा की नीतियों और विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अपना दल (एस) से पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह और सुधीर चौहान अपने समर्थकों के साथ सपा में हुए शामिल। वहीं, बीएसपी से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके विद्यासागर ने सपा का दामन थामा है। बसपा के कॉर्डिनेटर रहे लाल जी ने भी पार्टी ज्वाइन की है। जानकारी के मुताबिक, सपा ने आने वाले महीनों में प्रदेशभर में जनसभाएं, सम्मेलन और कार्यकर्ता बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई है।